>

Title: Need to check the high content of lead being used in paints affecting the health of children in the country.

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना विचार यहां रखने का मौका दिया। भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया) वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र संगठन है। इस संगठन ने एक अध्ययन लेड पॉयजनिंग के ऊपर किया है, जो सीसा का विष है और जिसके कुछ अंश समाचार-पत्रों में छपे हैं। अगर यह अध्ययन सही है, तो भारत की तरूणाई के ऊपर, भारत के बच्चों के ऊपर इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इस अध्ययन में यह पाया गया है कि 51.3 प्रतिशत बच्चे, जिनकी उम्र 12 साल से कम है, उनके रक्त में सीसे का लैवल 10 एमजी पर डेसी लिटर, जो एक सामान्य मात्रा मानी जाती है, उससे कहीं अधिक है। यह अध्ययन 23, 500 बच्चों के ऊपर जो छः महानगरों में रहते हैं, पांच साल के कार्यकाल में किया गया है। यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस इनक्रीज लेड कन्टेन्ट की वजह से सीधा-सीधा असर बच्चों के आई-क्यू लैवल्स पर पड़ता है, जो चार से छः प्वाइंट कम हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि जो रंग हमारे स्कूलों में इस्तेमाल किये जाते हैं, हमारे खिलौनों में इस्तेमाल किये जाते हैं, स्कूल बसों में इस्तेमाल किये जाते हैं, उनमें लेड कन्टेन्ट बहुत ज्यादा मात्रा में है। भारत में 93 प्रतिशत जो रंग बेचे जाते हैं, उनमें लेड का कन्टेन्ट इंटरनैशनल स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा है। इसका परिणाम यह होगा कि जब किसी बच्चे की कान्सेन्ट्रेट करने की क्षमता कम होती है या उसकी मानसिक फुर्ती में फर्क पड़ता है, तो माता-पिता उसे सीधा-सीधा सीसे के पॉयजनिंग से नहीं जोड़ पाते, क्योंकि उसे पकड़ना अत्याधिक मुश्किल है। आने वाले समय में जब 21वीं शताब्दी ज्ञान के ऊपर आधारित होगी, अगर इसी तरह से हमारी तरूणाई के आई-क्यू कम होते रहे, तो भारत की अर्थव्यवस्था को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान होगा। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्चा है, वह बहुत ज्यादा बढ़ जायेगा।

सभापति महोदय, वाणिज्य मंत्री यहां बैठे थे, मैं उम्मीद करता था कि वे हमारे बात सुनें, मगर वे शायद किसी काम से बाहर चले गये। मैं सरकार से दो सवाल करना चाहता हूं। वैसे जीरो ऑवर में सरकार को जवाब देना अधिकृत नहीं होता, पर क्योंकि बहुत ही गंभीर मसला है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि

क्या सरकार इस स्टडी को ऐक्सैप्ट करती है? अगर सरकार इस स्टडी को, इस अध्ययन को ऐक्सैप्ट करती है, तो इस बारे में क्या करने वाली है? यह दो सवाल मैं सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।